

accounts and the names of officias who ignored this fact and the action proposed to be taken against them;

(c) whether there are other trade unions which did not submit proper and actual annual returns and their registration was not cancelled; and

(d) if so, the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (d). The Registrar of Trade Unions, Delhi Administration has reported that registrations of 106 Trade Unions were cancelled in July, 1982 for non-submission of annual returns for the year 1977 under Section 10 of the Trade Unions Act, 1926. The registrations of those trade unions which were registered towards the end of 1977 were, however, not cancelled, because the registration of a particular union for non-submission of annual return is only cancelled when the union has actually worked for substantial period of the year of cancellation. The registration of Food Corporation of India Employees' Union, which was registered on 31-8-77 with scope of membership throughout the country had only 55 members at the time of registration as against 56,199, shown in the combined return upto 1978, was not cancelled as it was expected that the real tempo of enrolment of members and income and expenditure of different committees, as mentioned in its constitution, could only be done after few months of its registration. Moreover, after registration it had submitted combined annual return for the year 1978 on 31-5-79 and thereafter it has also submitted returns for the years 1979 and 1980.

डाक-तार विभाग की सलाहकार समिति में संसद सदस्यों की यात्रा तथा दैनिक भत्ता शामिल

3609. श्री रामावतार शास्त्री: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति डाक-तार विभाग की

हिन्दी सलाहकार समिति तथा अन्य ऐसी सलाहकार समितियों में भाग लेने वाले संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को अधिशासित करने वाले नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अदा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सिकरिल स्तर पर गठित डाक-तार सलाहकार समिति तथा टेलीफोन सलाहकार समितियों में शामिल संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता अदा नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण तथा क्या यह कथित नियमों को उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां ।

(ख) सिकरिल स्तर पर गठित डाक तार सलाहकार समिति और टेलीफोन सलाहकार समितियों में संसद सदस्यों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय के का. जा. सं. 19049/1/81-पी-चार दिनांक 16-3-1981 के अनुसार दैनिक भत्ता तथा संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के खंड-4 के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Promotion to Officers in P&T Directorate and Telecommunication Research Centre

3610. SHRI CHANDRA PAL SHAILANI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether some officers in P&T Directorate and Telecommunication Research Centre have been promoted from Telecommunication Engineering Service Group B to TES Group 'A' on ad hoc/local arrangement basis during last three years in 1980, 1981 and 1982;